



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2016/आश्विन 22, 1938

No. 329]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2016/ASVINA 22, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2016

विषय : जापान और कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरूआत

सं. 14/31/2015-डीजीएडी: —यतः मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा संबद्ध वस्तु के चार उत्पादकों अर्थात् मै. डीसीडब्लू लि., मै. गुजरात अलकलीज एंड कैमिकल्स लि., मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और एसआईईएल (जिसे एतदपश्चात आवेदक या याचिकाकर्ता भी कहा गया है) के साथ कास्टिक सोडा के घरेलू उत्पादकों की ओर से 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिधारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष जापान और कतर (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. कथित रूप से पाटित की जा रही वस्तु कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा को रासायनिक रूप से एनएओएच या सोडियम हाइड्रॉक्साइड के रूप में जाना जाता है। कास्टिक सोडा एक साबुनी, अधिक अल्कलाइन गंधरहित द्रव होता है।

कास्टिक सोडा को तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं अर्थात मरकरी सेल प्रक्रिया, डायफ्रेम प्रक्रिया और मेम्बरेन प्रक्रिया द्वारा दो रूपों अर्थात लाई और ठोस (फ्लेक्स) रूप में उत्पादित किया जाता है। द्रव रूप को ठोस रूप में बदला जा सकता है और ठोस रूप को आसानी से उत्पाद की रासायनिक विशेषताओं में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव में पुनः बदला जा सकता है। ठोस रूप के भण्डारण और परिवहन में आसानी होती है जबकि द्रव रूप आसानी से घुल जाता है। अंतिम प्रयोग के लिए दोनों रूप प्रतिस्थापनीय और अंतर स्थापनीय हैं। कास्टिक सोडा के दोनों रूप इस जॉच की विषय वस्तु हैं।

ख. समान वस्तु

3. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोइ ज्ञात अंतर नहीं है।

ग. सीमाशुल्क वर्गीकरण

4. कास्टिक सोडा को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। आईटीसी 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, इस उत्पाद को सीमाशुल्क शीर्ष 2815.1101, 2815.1102 और 2815.1200 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि उक्त वर्गीकरण के बल साकेतिक हैं और इस जॉच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

5. यह याचिका मै. अल्कली मेन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा संबद्ध वस्तु के चार उत्पादकों अर्थात मै. डीसीडब्लू लि., मै. गुजरात अलकलीज एंड कैमिकल्स लि., मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. और एसआईईएल के साथ संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों की ओर से दायर की गई है।

6. उक्त भागीदार कंपनियों के अलावा विचाराधीन उत्पाद के 25 अन्य भारतीय उत्पादक भी हैं जो एसोसिएशनों के सदस्य भी हैं। एसोसिएशन द्वारा प्रदत्त सभी घरेलू उत्पादकों की क्षमताओं और उत्पादन की मात्रा संबंधी सूचना के अनुसार भागीदार घरेलू उत्पादकों का भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस जॉच के प्रयोजनार्थ आवेदक घरेलू उद्योग के पास नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार वह घरेलू उद्योग हैं।

इ. शामिल देश

7. वे देश जिनके विरुद्ध जॉच करने के लिए आवेदन दायर किया गया है जापान और कतर हैं।

च. पाटन मार्जिन का अनुमान

8. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन के साध्य के रूप में जॉच अवधिके लिए एचआईएच कैमिकल, ग्लोबल क्लोर अल्कली, मासिक बाजार रिपोर्ट का संदर्भ लिया गया है जो अम.डा./डीएमटी के रूप में जापान/एनई एशिया और मध्य पूर्व की घरेलू कीमतों को दर्शाते हैं। तदनुसार, जापान के लिए कारखाना-द्वार सामान्य मूल्य का अनुमान जापान के घरेलू बाजार में औसत बिक्री कीमत के आधार पर उसे घरेलू बिक्री व्ययों के लिए समायोजित करने के बाद लगाया गया है। खाड़ी क्षेत्र में संबद्ध वस्तु के लिए व्यापार कीमतों की किसी प्रकाशित सूचना के अभाव में कतर के लिए सामान्य मूल्य का आकलन प्रारंभिक अनुमानों के प्रयोजनार्थ परिकलित किया गया है।

9. उक्त देशों के लिए निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत का अनुमान डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतरर्देशीय भाड़ा व्ययों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समायोजन करते हुए लगाया गया है।

10. प्राधिकारी के समक्ष आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के अनुसार संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य भारत में निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाठन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाठन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

11. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाठित आयातों से मात्रा और कीमत प्रभावों के संचयी प्रभावों के कारण बाजार हिस्से और लाभप्रदता में गिरावट के अनुसार वास्तविक क्षति हुई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि जाँच की प्रस्तावित अवधि में पाठित आयातों में वृद्धि की दर से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है। आवेदक ने संबद्ध देशों से पाठित आयातों की मात्रा और मूल्य और विचाराधीन उत्पाद के कथित पाठित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे को सिद्ध करते हुए विभिन्न मापदंडों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। इन मापदंडों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाठित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और निकट भविष्य में भी क्षति का खतरा है।

ज. पाठनरोधी जाँच की शुरूआत

12. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाठनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाठन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे तथा पाठन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाठनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाठन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाठन, यदि कोई हो, की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाठनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

क) जाँच अवधि (पीओआई)

13. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ 1 अप्रैल, 2015 - 31 मार्च, 2016 तक की अवधि जाँच अवधि (पीओआई) होगी। तथापि क्षति जाँच 2012- 2013, 2013- 2014, 2014- 2015 और जाँच की अवधि (पीओआई) की सूचना पर विचार किया जाएगा।

ख) सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए जापान और कतर की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाठनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

ग) समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जाँच की शुरूआत के पत्र की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष, जिसका पता उपलब्ध न हो, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है। सूचना हार्ड कॉपी और साफ्ट कॉपियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाठनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

घ) गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

- (क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और
- (ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि)।

18. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

19. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं। सार्वक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

22. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड) सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. पाटनरोथी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

च) असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2016

Subject: Initiation of Antidumping Investigation against import of Caustic Soda originating in or exported from Japan and Qatar.

F. No. 14/31/2015-DGAD:—WHEREAS a petition has been filed by the Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), before the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), on behalf of the domestic producers of caustic soda, along with 4 producers of the subject goods, i.e., M/s DCW Ltd, M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., M/s Grasim Industries Ltd., and SIEL (hereinafter referred to as the Applicants or Petitioners) requesting for initiation of an anti-dumping investigation against import of Caustic Soda (herein after referred to as subject goods) originating in or exported from Japan and Qatar (hereinafter referred to as subject countries), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as Rules).

A. Product under consideration

2. The goods allegedly being dumped are Caustic Soda. Caustic Soda is chemically known as NaOH, an inorganic, soapy, strongly alkaline and odorless chemical. Caustic Soda is produced in two forms i.e. lye and solids (flakes) by three technology processes, i.e. mercury cell process, diaphragm process and membrane process. Liquid form can be converted into solid and solid form can be reconverted in liquid with ease and without any change in the chemical properties of the product. The solid form has ease of storage and transportation whereas the liquid form has easy solubility. For end use both the forms are substitutable and interchangeable. Both the form of caustic soda are subject matters of this investigation.

B. Like article

3. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods produced by the Indian industry and subject goods imported into India from the subject countries.

C. Customs Classification

4. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under the customs heads 2815.11 and 2815.12. As per the ITC 8-digit classification the product is classified under the Custom Heading 2815.1101, 28151102 and 2815.1200. However, the above classification is indicative only and is no way binding on the scope of this investigation.

D. Domestic industry and Standing

5. The petition has been filed by the Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of Indian producers of the subject goods alongwith 4 major producers of the subject goods i.e., M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., M/s DCW Ltd., M/s Grasim Industries Ltd, M/s SIEL.

6. Apart from the above participating companies there are about 25 other Indian producers of the product under consideration who are also members of the associations. As per the information on the capacities and production volumes of all domestic producers provided by the Association the participating domestic producers command a major proportion of the production of the subject goods in India. Therefore, the Authority holds that for the purpose of this investigation the applicant domestic producers command the standing in terms of Rule 5(3) and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

E. Countries Involved

7. The countries against whom the application has been filed for investigation are Japan and Qatar.

F. Estimates of Dumping Margin

8. As evidence of dumping of the subject goods from the subject countries the HIS Chemical, Global Chlor Alkali, Monthly Market Reports for the period under investigation has been referred to which provides the domestic prices in Japan/NE Asia and Middle East in terms of US\$/ DMT. Accordingly, the ex-works normal value in Japan has been estimated on the basis of this information the average selling price in the domestic market in Japan after adjusting the same for the domestic selling expenses. In the absence of published information of the trading prices for the subject goods in Gulf region the Normal value in Qatar has been constructed for the purpose of preliminary estimates.

9. The net ex-works export prices from the above countries have been estimated considering volume and value of imports as per DGCI&S data after adjusting the same for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses on facts available basis.

10. As per the positive evidence placed by the applicants before the Authority the Normal Values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices to India, indicating *prima facie* that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject countries. The dumping margins so estimated, are positive and above *de minimis*.

G. Injury and causal link

11. The petitioners have alleged that dumped imports of the subject goods from the subject countries have caused material injury in terms of erosion of market share and profitability due to cumulative effects of volume and price effects. It has also been alleged that the rate of increase in dumped imports in the proposed period of investigation is causing threat of material injury to the domestic industry. The applicant has furnished information on volume and value of dumped imports from the subject countries and various parameters establishing injury and threat of material injury to the domestic industry, on account of the alleged dumped import of the product under consideration. These parameters *prima facie* indicate that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports of the subject goods from the subject countries and there is a threat of injury in the imminent future.

H. Initiation of anti-dumping investigations

12. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient *prima facie* evidence of dumping of the subject goods from the subject countries; material injury and threat of material injury to the domestic industry; and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry, in terms of the Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping, if any, and to recommend the amount of antidumping duties, which if levied would be adequate to remove injury and threat of injury to the domestic industry.

I. Procedure

a) Period of investigation (POI)

13. For purpose of purpose of this investigation the period from 1st April 2015- 31st March 2016 shall be the period of investigation. However, for the purpose of injury investigation the information for the period 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI shall be considered.

b) Submission of information

14. The exporters in the subject countries; the Government of Japan and Qatar, through its Embassies in India; the importers and users of the subject goods in India; and the domestic industry are requested to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry

Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street,
New Delhi- 110001.

15. Any other interested party may also make its submissions, relevant to the investigation, in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

c) Time limit

16. All interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the ‘facts available’ on record in accordance with the AD Rules.

d) Submission of information on confidential basis

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof: -

(a) One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

(b) The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

19. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a ‘good cause’ statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

22. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

e) Inspection of Public File

23. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non- confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

f) Non-cooperation

24. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. and Designated Authority